

(2013) 3 एस. सी. आर. 1082

एम/एस आई. सी. डी. एस. लिमिटेड

बनाम

मैसूर आयकर आयुक्त व अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 3282)

14 जनवरी, 2013

(डी. के. जैन और जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.)

1. इन सभी अपीलों में, राजस्व द्वारा विशेष अनुमति देकर, कानून का सामान्य प्रश्न आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास के लिए निर्धारिती के दावे से संबंधित है। इसमें शामिल मूल्यांकन वर्ष 1991-1992 से 1996-1997 हैं।

2. निर्धारिती एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (टठप्) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह किराया खरीद, पट्टे और रियल एस्टेट आदि के व्यवसाय में लगा हुआ है। जिन वाहनों पर मूल्यह्रास का दावा किया गया था, उन्हें निर्धारिती द्वारा निर्माताओं को सीधे भुगतान के प्रति खरीदा गया बताया गया है। निर्धारिती ने, अपने व्यवसाय के एक हिस्से के रूप में, इन वाहनों

को अपने ग्राहकों को पट्टे पर दिया और उसके बाद, वाहनों के साथ उसका कोई भौतिक संबंध नहीं था। वास्तव में, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 (इसके बाद "एमवी अधिनियम "के रूप में संदर्भित) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में, पट्टेदारों को वाहनों के मालिकों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

3. प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए अपनी आय की रिटर्न में, निर्धारिती ने अन्य मदों के अलावा, कुछ परिसंपत्तियों (ट्रकों में किए गए अतिरिक्त) के संबंध में मूल्यह्रास का दावा किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्धारिती द्वारा वित्तपोषित किया गया था लेकिन तीसरे पक्ष के नाम पंजीकृत किया गया था। निर्धारिती ने इस आधार पर उच्च दर पर मूल्यह्रास का भी दावा किया कि वाहनों का उपयोग किराये पर चलाने के व्यवसाय में किया गया था।

4. मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यह्रास और उच्च दर दोनों के दावों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि निर्धारिती द्वारा इन वाहनों का उपयोग केवल दूसरों को पट्टे पर देने के माध्यम से किया गया था, न कि वाहनों को किराये पर चलाने के व्यवसाय में वास्तविक उपयोगकर्ता के रूप में। इसने केवल इन संपत्तियों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया था और वह न तो इन संपत्तियों का मालिक था और न ही उपयोगकर्ता था। व्यथित होकर निर्धारिती ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। जहां तक

सामान्य दर पर मूल्यह्रास का प्रश्न था, आयुक्त (अपील) निर्धारिती से सहमत थे। हालाँकि, उच्च दर पर मूल्यह्रास के लिए निर्धारिती के दावे को आयुक्त का समर्थन नहीं मिला।

5. असंतुष्ट होने पर, निर्धारिती और राजस्व दोनों ने मामले को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के समक्ष अपील में आगे बढ़ाया। ट्रिब्यूनल दोनों मामलों में निर्धारिती से सहमत था। सामान्य दर पर मूल्यह्रास के दावे के प्रश्न पर, ट्रिब्यूनल की निम्नलिखित टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं:

"वर्तमान मामले में निर्धारिती-अपीलकर्ता का व्यवसाय वाहनों और अन्य मशीनरी को पट्टे पर देना और किराये पर लेना है। यह निश्चित रूप से किराये की खरीद नहीं है, जैसा कि पट्टा समझौतों से देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ की प्रतियाँ रिकॉर्ड पर हैं। इसके अलावा, केवल मूल्यह्रास की अनुमति देना मौजूदा मामले में विवाद का विषय नहीं है। निचले अधिकारियों ने पहले ही सामान्य दरों में मूल्यह्रास की अनुमति दे दी है। इसलिए, वाहनों का स्वामित्व और उसका उपयोग मूल्यांकन अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष किसी भी स्तर पर विवादित नहीं है। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है, कि क्या वाहनों के पट्टेदारों ने उनके द्वारा उपयोग किए गए मूल्यह्रास का दावा किया है। इससे एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि पट्टेदारों ने मूल्यह्रास का दावा नहीं

किया है और यह अकेले अपीलकर्ता है जिसने वाहनों के वास्तविक मालिक होने के नाते मूल्यह्रास का दावा किया है। मूल्यह्रास की उच्च दर पर, ट्रिब्यूनल ने आयकर आयुक्त (अपील) की टिप्पणियों को निम्नानुसार खारिज कर दिया:

“सीआईटी (अपील) ने माना कि अपीलकर्ता ने केवल ट्रक खरीदने के लिए वित्त पोषण किया है। इसलिए, उनके अनुसार, ट्रकों को पट्टे पर देना या उन्हें किराए पर लेना ट्रकों को किराए पर लेने का व्यवसाय करने जैसा नहीं है। सीआईटी (अपील) के अनुसार अपीलकर्ता को मूल्यह्रास की उच्च दर का दावा करने के लिए ट्रकों को किराये पर चलाने के अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन अपीलकर्ता की मुख्य गतिविधि ट्रकों को दूसरों को पट्टे पर देना या किराए पर देना है।

” ” ” सीआईटी (अपील) की राय में, नियमों में इस्तेमाल की गई भाषा में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ मूल्यह्रास भत्ता केवल तभी उपलब्ध है जब ट्रकों का उपयोग उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में किया जाता है। अपीलकर्ता का केवल पट्टे पर देने का व्यवसाय है और वह जनता के लिए ट्रक किराये पर लेने का व्यवसाय नहीं चलाता है। विभाग के अनुसार अंतर बहुत स्पष्ट है और अपीलकर्ता के पास ट्रकों को किराए पर लेने के व्यवसाय पर बढ़े हुए मूल्यह्रास का दावा करने का कोई मामला नहीं है।

6. आयकर आयुक्त, कर्नाटक, बेंगलोर बनाम शान फाइनेंस (पी) लिमिटेड, बेंगलोर में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने माना कि निर्धारिती, जिसने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ट्रकों का उपयोग किया था, उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए ट्रकों पर 50% की उच्च मूल्यह्रास दर का हकदार था।

7. व्यथित होकर, राजस्व ने अधिनियम की धारा 260ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए: -

“क्या अपीलकर्ता (निर्धारिती) उन वाहनों का मालिक है जो उसने अपने ग्राहकों को पट्टे पर दिए हैं और क्या अपीलकर्ता (निर्धारिती) उक्त वाहनों पर मूल्यह्रास की उच्च दर का हकदार है, इस आधार पर कि वे किराए पर दिए गए थे अपीलकर्ता के ग्राहकों के लिए।”

8. राजस्व के पक्ष में दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाहन निर्धारिती के नाम पर पंजीकृत नहीं थे, और निर्धारिती ने केवल लेनदेन को वित्तपोषित किया था, इसे आयोजित नहीं किया जा सकता है वाहनों का मालिक होने के नाते, और इस प्रकार, इन वाहनों के संबंध में मूल्यह्रास का दावा करने का हकदार नहीं था। इसलिए, निर्धारिती द्वारा ये अपीलें दायर कि गईं।

9. मौजूदा विवाद के लिए प्रासंगिक मूल्यह्रास अधिनियम की धारा

32 इस प्रकार है:

“32.(1) मूल्यह्रास के संबंध में-

(प) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जो मूर्त संपत्ति हैं;

(पप) जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिह्न, लाइसेंस, फ्रैंचाइजी या समान प्रकृति का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति, स्वामित्व, पूर्ण या आंशिक रूप से, द्वारा निर्धारिती और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने पर, निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी जाएगी-

प) बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में लगे किसी उपक्रम की परिसंपत्तियों के मामले में, निर्धारिती को उसकी वास्तविक लागत पर ऐसा प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है;)

पप) संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के मामले में, उसके लिखित मूल्य पर ऐसा प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी-

(ए) भारत के बाहर निर्मित कोई भी मोटर कार, जहां ऐसी मोटर कार निर्धारिती द्वारा 28 फरवरी, 1975 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2001 से पहले हासिल की जाती है, जब तक कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है-

प) पर्यटकों के लिए इसे किराये पर चलाने के व्यवसाय में; या

पप) भारत से बाहर किसी अन्य देश में अपने व्यवसाय या पेशे में; और
(बी) कोई भी मशीनरी या संयंत्र, यदि उसकी वास्तविक लागत को धारा
42 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए समझौते के तहत एक या अधिक
वर्षों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि जहां खंड (प) या
खंड में निर्दिष्ट संपत्ति हो (पप) या खंड (पपए) जैसा भी मामला हो, पिछले
वर्ष के दौरान निर्धारित द्वारा अर्जित किया गया है और उस पिछले वर्ष में
एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों
के लिए उपयोग में लाया गया है, इस उप के अंतर्गत कटौती ऐसी
परिसंपत्ति के संबंध में अनुभाग, जैसा भी मामला हो, खंड (प) या खंड
(पप) (या खंड (पपए) के तहत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत पर
गणना की गई राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

10. मूल्यह्रास एक पूंजीगत संपत्ति में आई टूट-फूट का मौद्रिक
समतुल्य है जिसे परिसंपत्ति के बेकार हो जाने पर उसके प्रतिस्थापन की
सुविधा के लिए अलग रखा जाता है। पी के बदियानी बनाम आयकर
आयुक्त, बॉम्बे, इस न्यायालय ने देखा है कि मूल्यह्रास के लिए भत्ता किसी
परिसंपत्ति के मूल्य को उस सीमा तक प्रतिस्थापित करना है, जिस हद तक
मूल्यांकन वर्ष से संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान इसका मूल्यह्रास हुआ
है और जैसा कि मूल्य है, उस तक सीमा, खो जाने पर, मूल्यह्रास के लिए
तदनुरूपी भत्ता प्राप्त होता है।

11. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण) अन्य बातों के साथ-साथ

'मूल्यहास' को परिभाषित करता है:

"मूल्य में गिरावट; मूल्य में कमी उम्र, उपयोग के कारण मूल्य में गिरावट या हानि या कमी और बेहतर तरीकों से सुधार। टूट-फूट या अप्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती है और इसे आमतौर पर एक निर्धारित सूत्र द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति के उपयोगी जीवन की एक निश्चित अवधि में इन तत्वों को दर्शाता है... अनुमानित उपयोगी से अधिक पूंजी निवेश की लागत का अनुमान लगाने और आवंटित करने की लगातार क्रमिक प्रक्रिया कमाई के मुकाबले लागत का मिलान करने के लिए परिसंपत्ति का जीवन..." छठा संस्करण अन्य बातों के साथ-साथ इसे निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित करता है:

"लेखांकन में, किसी पूंजीगत संपत्ति की लागत को उसके अनुमानित उपयोगी जीवन तक फैलाना।

टूट-फूट या अप्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती है और इसे आमतौर पर एक निर्धारित सूत्र द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति के उपयोगी जीवन की एक निश्चित अवधि में इन तत्वों को दर्शाता है।

12. पाक्स इन पिरसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन (पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ 323 पर) कहता है: जहाँ तक निर्माण की बात है, मूल्यहास उपभोग, उपयोग या समय के व्यय के माध्यम से घिसाव का माप है।

पैटन ने अपने अकाउंट की हैंडबुक (तीसरा संस्करण) में कहा है कि मूल्यह्रास किसी भी अन्य लागत की तरह जेब से बाहर की लागत है। उन्होंने आगे कहा है- मूल्यह्रास शुल्क केवल अचल संपत्ति लागत का आवधिक परिचालन पहलू है।

13. अधिनियम में मूल्यह्रास पर प्रावधान में कहा गया है कि संपत्ति का स्वामित्व, पूर्ण या आंशिक रूप से, निर्धारिती के पास होना चाहिए और व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 32 के तहत एक सफल दावे के लिए 'स्वामित्व और 'व्यवसाय के लिए उपयोग' की दोहरी आवश्यकता लगाता है।

14. राजस्व ने अनुभाग के इस हिस्से के दोनों चरणों पर यह तर्क देकर हमला किया: (प) कि निर्धारिती प्रश्न में वाहनों का मालिक नहीं है और (पप) कि निर्धारिती ने अपने व्यवसाय के दौरान इन ट्रकों का उपयोग नहीं किया। यह तर्क दिया गया कि मूल्यह्रास का दावा एक निर्धारिती द्वारा केवल उस मामले में किया जा सकता है जहां निर्धारिती संपत्ति का मालिक और उपयोगकर्ता दोनों हैं।

15. हम पहले विवाद पर विचार करने से पहले दूसरे विवाद का निपटारा करना चाहेंगे। राजस्व ने तर्क दिया कि चूंकि पट्टेदार वास्तव में वाहनों का उपयोग कर रहे थे, वे मूल्यह्रास का दावा करने के हकदार थे, न कि निर्धारिती। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। धारा के अनुसार निर्धारिती

को संपत्ति का उपयोग "व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। यह निर्धारिती द्वारा परिसंपत्ति के उपयोग को अनिवार्य नहीं करता है। जब तक परिसंपत्ति का उपयोग निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जाता है, तब तक धारा 32 की आवश्यकता पूरी होगी, भले ही निर्धारिती द्वारा परिसंपत्ति का उपयोग न किया जाए। हमारे सामने मौजूदा मामले में, निर्धारिती एक लीजिंग कंपनी है जो खरीदे गए ट्रकों को पट्टे पर देती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 2(13) और धारा 2(24) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर , ट्रकों को पट्टे पर देने से प्राप्त आय व्यावसायिक आय होगी, या व्यवसाय के दौरान प्राप्त आय होगी, और ऐसा मूल्यांकन किया गया है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 32 की उपरोक्त दूसरी आवश्यकता को पूरा करता है कि परिसंपत्ति का उपयोग व्यवसाय के दौरान किया जाना चाहिए।

16. शान फाइनेंस (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 32 ए(2) और धारा 33 के अनुरूप प्रावधानों के मामले में "व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करते हुए, क्रमशः निवेश भत्ते और विकास छूट के साथ, इस प्रकार आयोजित:

-“9. हालाँकि, धारा 32-ए की उप-धारा (2) की जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उस उप-धारा में कोई प्रावधान है जिसके लिए आवश्यक है कि निर्धारिती को केवल अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए

मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं निर्माण के प्रयोजन के लिए या मशीनरी को जिस अन्य प्रयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसके लिए मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। उपधारा (2) में वे सभी मदें शामिल हैं जिनके संबंध में निवेश भत्ता दिया जा सकता है। ये वस्तुएं हैं, जहाज, विमान या मशीनरी या उस उप-धारा में निर्दिष्ट कुछ प्रकार के संयंत्र। एक नए जहाज या नए विमान के संबंध में, धारा 32-ए (2) (ए) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि नए जहाज या नए विमान को एक निर्धारिती द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए जो खुद जहाजों या विमान के संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है। उप-धारा (2)(बी) के तहत, हालांकि, ऐसी कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है कि निर्धारिती को स्वयं संयंत्र या मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। धारा 32-ए(2)(बी) केवल नए संयंत्र या मशीनरी का वर्णन करती है जो धारा 32-ए के अंतर्गत आती है। संयंत्र या मशीनरी का वर्णन उसके उद्देश्य के संदर्भ में किया गया है। उदाहरण के लिए, उप-धारा (2)(बी)(प) "बिजली या किसी अन्य प्रकार की बिजली के उत्पादन या वितरण के व्यवसाय के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। उप-धारा (2)(बी)(पप) छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को संदर्भित करता है जो व्यवसाय या किसी भी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, और उप-धारा (2)(बी)(पपप) संदर्भित करता है ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी वस्तु या चीज के निर्माण, निर्माण या उत्पादन का व्यवसाय। इसलिए, उप- धारा 2(बी) उन

उपयोगों को संदर्भित करता है जिनके लिए मशीनरी लगाई जा सकती है। यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि निर्धारिती को स्वयं इन उद्देश्यों के लिए मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान मामले में, जिस व्यक्ति को मशीनरी किराए पर दी गई है वह धारा 32-ए(2)(बी)(पपप) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए मशीनरी का उपयोग करता है हालाँकि, वह व्यक्ति मशीनरी का मालिक नहीं है। कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों ने माना है कि धारा 32-ए में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए , वर्तमान मामले में, करदाता उस धारा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात्, (1) मशीनरी करदाता के स्वामित्व में है; (2) मशीनरी का उपयोग निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए किया जाता है और; (3) मशीनरी उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

10. हम कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों के इस तर्क से सहमत हैं।

17. इसी निर्णय ने विकास छूट पर धारा 33 की अनुरूप प्रकृति पर टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि वाक्यांश "व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है" के लिए संपत्ति के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया:

"11. निवेश भत्ते से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 के तहत विकास छूट से संबंधित प्रावधानों के समान हैं ... "" "" ""

12. चूंकि विकास छूट से संबंधित धारा 33 के प्रावधान धारा 32-ए के प्रावधानों के समान हैं , इसलिए धारा के तहत विकास छूट के अनुदान से संबंधित मामलों को देखना आवश्यक है।

33. सीआईटी बनाम कैस्टलरॉक फिशरीज (1980) 126 आईटीआर 382 के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने एक निर्धारिती के मामले पर विचार किया जिसने अस्थायी रूप से अपने कोल्ड-स्टोरेज प्लांट को एक सहायक कंपनी को दे दिया था। इस तरह के किराये से प्राप्त आय का मूल्यांकन आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारिती के सामने प्रासंगिक लेखांकन वर्षों के लिए निर्धारिती की व्यावसायिक आय के रूप में किया गया था। निर्धारिती ने कोल्ड-स्टोरेज प्लांट के संबंध में विकास छूट का दावा किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि विभाग ने यह स्वीकार किया है कि संयंत्र और मशीनरी को किराये पर देने में, निर्धारिती अभी भी व्यवसाय कर रहा था और उसे जो किराया शुल्क प्राप्त हुआ था, उसका मूल्यांकन करदाता की व्यावसायिक आय के रूप में किया गया था। इसलिए निर्धारिती ने विकास छूट के अनुदान के लिए सभी शर्तों का अनुपालन की थी, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि निर्धारिती ने अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए मशीनरी का उपयोग किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसलिए, यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि धारा 33(1)(ए) में निर्धारित शर्तें कि मशीनरी या संयंत्र का उपयोग करदाता द्वारा किए गए व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से किया जाता है, विधिवत संतुष्ट हैं और

निर्धारिती विकास छूट का हकदार है। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने सीआईटी बनाम कैसल रॉक फिशरीज (1997) 10 एससीसी 77 में उपरोक्त मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने यह भी माना कि चूंकि विभाग आगे बढ़ चुका है स्पष्ट आधार पर कि इस तथ्य के बावजूद कि संयंत्र को निर्धारिती द्वारा अस्थायी रूप से एक सहयोगी संस्था को किराए पर दे दिया गया था, फिर भी संयंत्र और मशीनरी का उपयोग निर्धारिती द्वारा अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, इस तरह के किराए से निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय का इलाज करके निर्धारिती की व्यावसायिक आय के रूप में, विकास छूट को उचित रूप से प्रदान किया गया माना जाना चाहिए। इसलिए, जहां निर्धारिती के व्यवसाय में मशीनरी को किराए पर लेना शामिल है और/या जहां ऐसी मशीनरी को किराए पर लेने से निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय व्यावसायिक आय है, तो निर्धारिती को अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए मशीनरी का उपयोग करने वाला माना जाना चाहिए।

13. इसी तरह का दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम विनोद भार्गव (1988) 169 आईटीआर 549 (एपी) के मामले में लिया है, जहां जीवन रेड्डी, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने माना था कि निर्धारिती द्वारा मशीनरी को पट्टे पर देना व्यवसाय चलाने का एक तरीका है, निर्धारिती विकास छूट का हकदार होगा। न्यायालय ने कहा (पृ. 551

“(ओ) यह माना जाता है कि मशीनरी को पट्टे पर देना निर्धारिती द्वारा व्यवसाय करने का एक तरीका है और पट्टे से प्राप्त आय को व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है, यह कहना विरोधाभासी होगा कि मशीनरी निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं की जाती है।”

18. इसलिए, निर्धारिती दूसरी आवश्यकता को पूरा करता है।

निर्धारिती ने अपने पट्टे के व्यवसाय के दौरान वाहनों का उपयोग किया।

हमारी राय में, यह तथ्य कि ट्रकों का उपयोग निर्धारिती द्वारा नहीं किया

गया था, अनुभाग के प्रयोजन के लिए अप्रासंगिक है।

19. अब हम पहली आवश्यकता अर्थात् स्वामित्व के मुद्दे पर विचार

कर सकते हैं। किसी भी पूंजीगत व्यय के संबंध में कोई मूल्यह्रास भत्ता

नहीं दिया जाता है जिसे निर्धारिती दूसरों की संपत्ति पर खर्च करने के लिए

बाध्य हो सकता है। इसलिए, पूरा मामला स्वामित्व के सवाल पर टिका है;

यदि निर्धारिती वाहनों का मालिक है, तो वह मूल्यह्रास पर दावे का हकदार

होगा, अन्यथा नहीं।

20. मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, एमजी रोड, बेंगलोर बनाम आयकर

आयुक्त, कर्नाटक, बेंगलोर, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“ अधिकारियों बताते हैं कि मूल्यह्रास की अवधारणा से पता चलता है कि

मूल्यह्रास के कारण कर लाभ वैध रूप से उसी का है जिसने पूंजीगत संपत्ति

में निवेश किया है, पूंजीगत संपत्ति का उपयोग कर रहा है और इस तरह धीरे-धीरे टूट-फूट के कारण निवेश खो रहा है, और इसकी आवश्यकता होगी समय के साथ इसका मूल्य पूरी तरह से खो जाने पर इसे प्रतिस्थापित करें।”

21. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) 'मालिक' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

“मालिक। वह व्यक्ति जिसमें संपत्ति का स्वामित्व, प्रभुत्व या शीर्षक निहित है; मालिक। वह जिसका किसी वस्तु पर प्रभुत्व है, वास्तविक या व्यक्तिगत, साकार या निराकार, जिसका उसे आनंद लेने और उसके साथ अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने का अधिकार है, यहां तक कि जहां तक कानून अनुमति देता है, उसे खराब करने या नष्ट करने का भी अधिकार है, जब तक कि उसे कुछ लोगों द्वारा रोका न जाए। समझौता या अनुबंध जो उसके अधिकार को रोकता है।

हालाँकि, यह शब्द एक नामकरण सामान्यीकरण है, और इसका अर्थ उस संबंध से इकट्ठा किया जाना है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, और उस विषय-वस्तु से जिस पर इसे लागू किया जाता है। भूमि पर लागू होने वाले शब्द का प्राथमिक अर्थ वह है जो शुल्क का मालिक है और जिसके पास संपत्ति का निपटान करने का अधिकार है, लेकिन शर्तों में

भूमि पर स्वामित्व का अधिकार रखने वाला या उस पर कब्जा करने या खेती करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।

“मालिक” शब्द का उपयोग उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसमें एक या अधिक हित निहित होते हैं, उसका अपना लाभ होता है। जिस व्यक्ति में हित निहित हैं, उसके पास हितों पर ‘स्वामित्व’ है, चाहे वह उन्हें अपने लाभ के लिए रखता हो या किसी अन्य के लाभ के लिए। इस प्रकार शब्द “शीर्षक” “मालिक” के विपरीत है।” यह ‘स्वामित्व’ शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है - “संपत्ति का उपयोग करने और आनंद लेने के अधिकार का संग्रह, जिसमें इसे दूसरों को हस्तांतरित करने का अधिकार भी शामिल है... एक या अधिक व्यक्तियों का अधिकार किसी चीज़ को दूसरों को छोड़कर रखने या उपयोग करने का अधिकार। वह अधिकार जिसके द्वारा कोई चीज़ विशेष रूप से किसी एक की होती है, अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर। कब्जा, आनंद या निपटान का विशेष अधिकार; एक आवश्यक विशेषता के रूप में अधिकार को शामिल करना नियंत्रित करना, संभालना और निपटान करना।”

वही शब्दकोष “स्वयं” शब्द को ‘एक अच्छा कानूनी शीर्षक’ के रूप में परिभाषित करता है।

ये परिभाषाएँ अनिवार्य रूप से स्वामित्व को शेष विश्व के विरुद्ध कानूनी अधिकार या स्वामित्व का कार्य बनाती हैं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर

देखा गया है, यह "नोमेन जनरलिसिमम" है, और इसका अर्थ उस कनेक्शन से इकट्ठा किया जाना है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, और उस विषय-वस्तु से जिस पर इसे लागू किया जाता है।"

22. मौजूदा भौतिक तथ्यों की जांच से निर्धारिती के पक्ष में स्वामित्व का अनुमान लगाया जाता है। वाहन, उसकी चाबियों के साथ, निर्धारिती को सौंप दिया गया था, जिस पर, ग्राहक के साथ निर्धारिती द्वारा पट्टा समझौता किया गया था। इसके अलावा, निर्धारिती और ग्राहक के बीच समझौते के प्रासंगिक खंड विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि:

(प) निर्धारिती हर समय वाहन का एकमात्र मालिक था;

(पप) यदि पट्टेदार ने कोई चूक की है, तो निर्धारिती को वाहन को फिर से अपने कब्जे में लेने का अधिकार था (और न केवल ग्राहक से पैसे वसूलने के लिए);

(पपप) पट्टा अवधि के समापन पर, पट्टेदार निर्धारिती को वाहन वापस करने के लिए बाध्य था;

(पअ) निर्धारिती को हर समय वाहन के निरीक्षण का अधिकार था।

त्वरित संदर्भ के लिए, पट्टा समझौते के प्रासंगिक खंड यहां दिए गए हैं: -

"2. पट्टा किराया

करना होगा। इस तरह का मुआवजा यहां व्यक्त या निहित किसी भी नियम, शर्तों और समझौतों के तहत पट्टादाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिन-प्रतिदिन चलता रहेगा। इस तरह के बकाया का भुगतान प्राप्त करने में या उपकरणों के ठिकाने का पता लगाने का प्रयास करने में या उस पर कब्जा प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने में, चाहे कार्रवाई, मुकदमा या अन्यथा, पट्टेदार द्वारा किए गए सभी खर्च, इसके अतिरिक्त और इसके बिना, पट्टेदार से वसूल किए जाएंगे। इस पट्टे के उल्लंघन के लिए पट्टादाताओं के प्रति पूर्वाग्रह।

19. पट्टे की समाप्ति: इस पट्टे की समाप्ति पर, पट्टेदार पट्टेदार को परिसंपत्तियों को ऐसे स्थान पर वितरित करेगा जैसा कि पट्टेदार अच्छी मरम्मत, स्थिति और कार्यशील स्थिति में निर्दिष्ट कर सकता है। संपत्ति की वापसी होते ही पट्टादाता सुरक्षा जमा राशि वापस कर देगा। यदि पट्टेदार, पट्टेदार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार पट्टेदार को उपकरण वितरित करने में विफल रहता है, तो पट्टेदार को उसी किराये पर और यहां व्यक्त समान शर्तों पर संपत्ति का किरायेदार माना जाएगा और ऐसी किरायेदारी समाप्त की जा सकती है। पट्टेदार द्वारा डिफॉल्ट पर तुरंत या पहले दिए गए 7 दिनों के नोटिस पर..”

23. निर्धारिती के दावे पर राजस्व की आपत्ति पट्टा समझौते पर आधारित है। यह तर्क दिया गया कि पट्टे की अवधि के अंत में, वाहन का

स्वामित्व पट्टेदार को वाहन की मूल लागत के 10% तक के नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, जिससे निर्धारित वास्तव में एक वित्तपोषक बन जाता है। हालाँकि हम राजस्व से सहमत होने के लिए राजी नहीं हैं। जब तक करदाता के पास बाकी दुनिया के खिलाफ वाहन का कानूनी स्वामित्व बरकरार रखने का अधिकार है, तब तक वह कानून की नजर में वाहन का मालिक होगा। बिक्री समझौते की जांच वाहन के स्वामित्व के खिलाफ सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकती। स्वामित्व के सुराग पट्टा समझौते में ही निहित हैं, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित के पक्ष में इशारा करते हैं। हम इस संबंध में ट्रिब्यूनल की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमत हैं:

“20. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पट्टेदार द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी से लीज डीड के तहत वाहन का कब्जा लेने के बाद उसे अनुसूची में निर्धारित अनुसार लीज किराया का भुगतान करना होगा। पट्टे के समझौते के खंड (4) के अनुसार वाहनों का स्वामित्व अपीलकर्ता-कंपनी अर्थात् आईसीडीएस के पास होगा। लीज समझौते के खंड (9) के अनुसार, मै. आईसीडीएस को जब चाहे तब निरीक्षण का अधिकार है। लीज समझौते के खंड (18) के अनुसार, लीज किराया के भुगतान में चूक की स्थिति में, खर्च, ब्याज आदि के अलावा, अपीलकर्ता कंपनी उस वाहन पर कब्जा करने की हकदार है जिसे पट्टे पर दिया गया था। अंत में, खंड (19) के अनुसार, पट्टे की

अवधि समाप्त होने पर, पट्टेदार को वाहन को कार्यशील स्थिति में अपीलकर्ता कंपनी को वापस कर देना चाहिए।

21. यह सच है कि माल का पट्टा या किराये या किराये का समझौता एक अनुबंध है जिसके तहत इनाम के लिए एक पक्ष दूसरे को माल के उपयोग की अनुमति देता है। पट्टा एक निर्दिष्ट अवधि या शाश्वतता के लिए हो सकता है। एक पट्टा किराया खरीद समझौते से भिन्न होता है जिसमें पट्टेदार या किराएदार को सामान खरीदने का विकल्प नहीं दिया जाता है। किराया खरीद समझौते के विपरीत एक किराये का समझौता या पट्टा जमानत का एक अनुबंध है, जो स्पष्ट और सरल है जिसमें बिक्री का कोई तत्व निहित नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 में जमानत को परिभाषित किया गया है, "एक अनुबंध पर किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी, और जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटान किया जाएगा।"।

22. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती-अपीलकर्ता के व्यवसाय में होने वाले लेनदेन समझौते के तहत व पट्टे हैं, लेकिन किराया खरीद लेनदेन नहीं हैं। दरअसल ये 'भाड़े का लेन-देन है। यहां तक कि 'लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज' के लेखक के नजरिए से भी देखा जाए,

जिनके विचारों की चर्चा इस आदेश के पेज 16 और 17 में की गई थी, अपीलकर्ता व्यवसाय में शामिल लेनदेन लीज लेनदेन के अलावा और कुछ नहीं हैं।

23. जहां तक तथ्यात्मक हिस्से का सवाल है, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वाहनों को पट्टे पर देना वाहनों को किराये पर लेने के अलावा और कुछ नहीं है। ये दोनों पहलू एक ही हैं। हालाँकि, हम इस बिंदु पर दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत केस कानून पर चर्चा करेंगे।

24. निर्धारिती के दावे में एकमात्र बाधा, जो राजस्व के मामले की धुरी भी है, एम वी अधिनियम की धारा 2(30) है, जो स्वामित्व को इस प्रकार परिभाषित करती है: -

“मालिक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके नाम पर एक मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और एक मोटर वाहन के संबंध में जो किराया-खरीद समझौते का विषय है, या पट्टे का समझौता या दृष्टिबंधक का समझौता, उस समझौते के तहत वाहन के कब्जे में व्यक्ति।

25. धारा के सामान्य शुरुआती शब्द कहते हैं कि मोटर वाहन का मालिक वह है जिसके नाम पर वह पंजीकृत है, जो वर्तमान मामले में पट्टेदार है। लीजिंग समझौतों पर बाद के विशिष्ट बयान में कहा गया है कि लीज पर दिए गए वाहन के संबंध में, पट्टेदार जो कब्जे में है वह

मालिक होगा। इस प्रकार, राजस्व ने तर्क दिया कि वाहनों के स्वामित्व के मामले में, स्वामित्व का परीक्षण पंजीकरण और प्रमाणीकरण है। चूँकि प्रमाणपत्र पट्टेदार के नाम पर थे, वे वाहनों के कानूनी मालिक होंगे और मूल्यहास का दावा करने के हकदार होंगे। इसलिए, स्वामित्व पर सामान्य और विशिष्ट कथन स्वामित्व को पट्टेदार के पक्ष में मानते हैं, और इसलिए, राजस्व के पक्ष में हैं।

26. हम एक से अधिक कारणों से राजस्व के तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं: (प) धारा 2(30) एक ऐसा प्रावधान है जो केवल एम वी अधिनियम के प्रयोजन के लिए पट्टेदार के पक्ष में स्वामित्व की कानूनी कल्पना बनाता है। यह एम वी अधिनियम के बाद के प्रावधानों के लिए स्वामित्व को परिभाषित करता है, सामान्य रूप से कानून के उद्देश्य के लिए नहीं। यह एम वी अधिनियम की शर्तों का क्या अर्थ है, इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अधिक कार्य करता है। इसलिए, यदि एम वी अधिनियम किसी भी बिंदु पर किसी भी धारा में मालिक शब्द का उपयोग करता है, तो इसका मतलब यह है जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है और पट्टा समझौते के मामले में, पट्टेदार। बस इतना ही। यह सामान्य तौर पर स्वामित्व पर कानून का बयान नहीं है। शायद, स्वामित्व पर कानून के सामान्य विवरण का भंडार माल की बिक्री अधिनियम हो सकता है ; (पप) एमवी अधिनियम की धारा 2(30) को एमवी अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (4) और (5) के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जिसका उल्लेख वरिष्ठ

वकील श्री एस. गणेश ने किया था। निर्धारिती के लिए. प्रावधान इस प्रकार हैं:-

“(4) उक्त समझौते के तहत रखे गए किसी भी मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में कोई प्रविष्टि पंजीकरण प्रमाणपत्र में उस व्यक्ति की लिखित सहमति के अलावा नहीं की जाएगी जिसका नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किया गया है व व्यक्ति जिसके साथ पंजीकृत स्वामी ने उक्त समझौता किया है।

(5) जहां वह व्यक्ति जिसका नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र में उस व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने उक्त समझौता किया है, पंजीकरण प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसने पंजीकृत मालिक से वाहन का कब्जा ले लिया है। उक्त समझौते के प्रावधानों के तहत पंजीकृत मालिक की चूक और पंजीकृत मालिक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया है या फरार हो गया है, तो ऐसा प्राधिकारी, पंजीकृत मालिक को ऐसा प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद, जैसा वह करना चाहता है (उसे पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज उसके पते पर पावती देकर) और इसके बावजूद कि पंजीकरण प्रमाण पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रमाण पत्र रद्द करें और व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करें जिसके साथ पंजीकृत स्वामी ने उक्त समझौता किया है:

बशर्ते कि किसी मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है:

बशर्ते कि परिवहन वाहन के अलावा किसी मोटर वाहन के संबंध में जारी किया गया पंजीकरण का नया प्रमाणपत्र केवल उस शेष अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए इस उप-धारा के तहत रद्द किया गया प्रमाणपत्र लागू रहा होगा। इसलिए, एमवी अधिनियम यह आदेश देता है कि पट्टे की अवधि के दौरान, वाहन को पंजीकरण प्रमाणपत्र में, पट्टेदार के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए और, पट्टे की अवधि के समापन पर, वाहन को मालिक के रूप में पट्टादाता के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। यह धारा पट्टेदार के पास वाहन को पट्टेदार के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। इस प्रकार, पंजीकरण प्रमाणपत्र से वाहन के कानूनी स्वामित्व के स्वामित्व के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है; और (पपप) यदि पट्टेदार वास्तव में मालिक था, तो उसने वाहनों पर मूल्यहास का दावा किया होगा, जो कि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया गया होगा, जो कि नहीं किया गया था। स्वामित्व की शून्यता के कारण किसी विशेष मूल्यहास योग्य संपत्ति के मामले में मूल्यहास का कोई दावा नहीं करना एक अजीब स्थिति होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारिती द्वारा प्राप्त संपूर्ण पट्टा किराया उसके हाथों में व्यावसायिक आय के रूप में

मूल्यांकन किया गया है और पट्टेदार द्वारा भुगतान किए गए संपूर्ण पट्टा किराए को पट्टेदार के हाथों में कटौती योग्य राजस्व व्यय के रूप में माना गया है। यह इस स्थिति की पुष्टि करता है कि जहां तक अधिनियम की धारा 32 का संबंध है, निर्धारिती वास्तव में वाहन का मालिक है।

27. अंत में, निर्धारिती की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी राजस्व द्वारा स्वीकार किए गए और चुनौती न दिए गए बड़ी संख्या में मामलों की ओर इशारा किया, जिसमें पट्टादाता को पट्टा समझौते में संपत्ति के मालिक के रूप में रखा गया है। (आयकर आयुक्त बनाम. एएम कंस्ट्रक्शन्स; आयकर आयुक्त बनाम बंसल क्रेडिट्स लिमिटेड; आयकर आयुक्त बनाम. एमजीएफ (इंडिया) लिमिटेड; आयकर आयुक्त बनाम. अन्नामलाई फाइनेंस लिमिटेड। इनमें से प्रत्येक मामले में, पट्टे पर देने वाली कंपनी को परिसंपत्ति का मालिक माना गया था, और तदनुसार मूल्यहास का दावा करने और किराए पर दी गई संपत्ति पर लागू उच्च दर का दावा करने का हकदार माना गया था। उक्त बिंदु पर हम इन निर्णयों से पूरी तरह सहमत हैं।

28. निर्माता द्वारा जारी किए गए चालानों के संबंध में कुछ विवाद था - चाहे वे पट्टेदार या पट्टेदार के नाम पर जारी किए गए हों। हमने ऊपर जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके अनुसार हम उक्त प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक समझते हैं क्योंकि इसका मुख्य मुद्दे पर हमारी अंतिम

राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पट्टा समझौते और अन्य संबंधित कारकों के अवलोकन से, हम प्रश्न में ट्रकों के निर्धारिती के स्वामित्व से संतुष्ट हैं।

29. इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम मानते हैं कि पट्टेदार यानी निर्धारिती वाहनों का मालिक है। मालिक के रूप में, इसने अधिनियम की धारा 32 की दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अपने व्यवसाय के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया जो पट्टे पर दिए गए थे और इसलिए, ट्रकों में किए गए अतिरिक्त के संबंध में मूल्यह्रास का दावा करने का हकदार है।

30. मूल्यह्रास की उच्च दर के लिए निर्धारिती के दावे के संबंध में, अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे प्रावधान में उपयोग किए गए समान शब्द "व्यवसाय के उद्देश्य का आयात महत्व प्राप्त करता है। हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत इन शब्दों की व्याख्या उससे भिन्न नहीं होगी जो हमने पहले बताई थी। इसलिए, निर्धारिती उच्च मूल्यह्रास दर के दावे की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, और इसलिए उसका हकदार है।

31. इस संबंध में, हम ट्रिब्यूनल की निम्नलिखित टिप्पणियों का समर्थन करते हैं, जो मामले को निर्धारिती के पक्ष में तय करती है।

“15. सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 652, दिनांकित 14-6-1993 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किराए पर चलने वाली लॉरियों आदि के मामले में 40 की उच्च दर लागू नहीं होगी यदि वाहन का उपयोग निर्धारिती के गैर-किराए पर लेने वाले व्यवसाय में किया जाता है। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में उच्च प्रशंसा से इनकार करने के लिए इस परिपत्र को इसके संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है जब वास्तविक उपयोग किराए के व्यवसाय में होता हो।

(जोर दिया गया) शायद, लेखक का आशय यह था कि जब वाहन का वास्तविक उपयोग किराये के व्यवसाय में होता है, तो वह उच्च दर पर मूल्यह्रास का हकदार होता है।

39. शान फाइनेंस (पी) लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का सार यह है कि जहां निर्धारिती के व्यवसाय में मशीनरी को किराए पर देना शामिल है और/या जहां निर्धारिती द्वारा ऐसी मशीनरी को किराए पर लेने से आय प्राप्त होती है वहाँ निर्धारिती को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए मशीनरी का उपयोग करने वाला माना जाना चाहिए।

40. वर्तमान मामले में, निर्धारिती के व्यवसाय में मशीनरी और ट्रकों को किराए पर देना शामिल है, जहां ऐसी मशीनरी को किराए पर लेने से निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय व्यावसायिक आय है। इसलिए, निर्धारिती-

अपीलकर्ता अर्थात् आईसीडीएस को यह माना जाना चाहिए कि उसने ट्रकों का उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य से किया है।

41. हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 1998 के आईटीआरसी नंबर 789 में वर्ष 1986-87 में निर्धारिती के मामले में- अपीलकर्ता ने स्वयं (अर्थात् आईसीडीएस) पहले ही निर्धारिती के पक्ष में प्रश्न का निर्णय कर दिया है, सीआईटी (ए) और आईटीएटी के निर्णय की पुष्टि करते हुए कि निवेश भत्ते और अतिरिक्त मूल्यदास के लिए निर्धारिती कंपनी हकदार है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले में 231 आईटीआर 308 में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिलाइ किया गया था इसलिए हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि अपीलकर्ता- कंपनी अपने द्वारा पट्टे पर दिए गए ट्रकों पर 50 की उच्च मूल्यदास दर की हकदार है। इसलिए, हम इस मुद्दे पर सीआईटी (अपील) के आदेशों को उलटते हैं।

32. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को उलटने में कानूनी गलती की। परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं; आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है और पैरा 7 (सुप्रा) में निकाले गए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया जाता है।

हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।